विकास की राह पर 5000 दिन पूरा करता छत्तीसगढ़

रमन ने खाए मनरेगा मज़दूर के बनाए भात, अमारी भाजी और लकड़ा चटनी

मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को मनरेगा की मजदूर उर्मिला कोर्राम ने खिलाया भात के साथ अमारी भाजी ,अमारी की चटनी । दूसरी मजदूर महिला मानमति यादव ने खिलाया तेन्दू । बिलासपुर जिले के ग्राम गौरखेड़ी (विकासखण्ड गौरेला) का वाकया । मुख्यमंत्री लोक सुराज अभियान के तहत आज रायपुर से हेलिकॉप्टर द्वारा रवाना होकर सबसे पहले इसी गाँव के निर्माणाधीन बाँध स्थल पर पहुंचे । वहां 33 करोड़ की लागत से बन रहे बाँध को देखा । इसके बन जाने पर रबी और खरीफ में 541 किसानों के कुल 1600 हेक्टेयर खेतों में होगी सिंचाई । मुख्यमंत्री ने मनरेगा का मस्टर रोल देखा । मजदूरों से मजदूरी भुगतान के बारे में पूछा । एक जगह चल रहे मनरेगा का काम देखने पैदल गए । गौरखेडा में महिला स्वसहायता समूह द्वारा संचालित राशन दुकान के बारे में ग्रामीणों से कुछ शिकायतें मिली । मुख्यमंत्री ने दुकान को सील करने और ग्रामीणों के आग्रह पर सहकारी समिति (लैम्प्स) को देने का लिया निर्णय । मनरेगा मजदूर उर्मिला कोर्राम को कुआं निर्माण की मंजूरी दी ।

119 साल पुराने थाने में पहुंचे डॉ. रमन सिंह

रायपुर। लोक सुराज अभियान के तहत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वहां जनता से सीधे रूबरू हो रहे छत्तीसगढ़ के सीएम डॉ. रमन सिंह धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक पहुंचे। यहां सिहावा में स्थित आजादी से पहले बने थाने और वहां रखे पुराने दस्तावेजों को देखा। यहां पहुंचकर डॉ. रमन सिंह काफी एक्साइटेड दिखे।

लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री महानदी के उद्गम स्थल सिहावा पहुंचे। यहां उन्होंने 119 साल पुराने थाने का औचक निरीक्षण किया। महर्षि श्रृंगी ऋषि के आश्रम के नीचे का यह इलाका काफी पहले बस्तर अंचल का हिस्सा था।

अभिलेखों के अनुसार ब्रिटिश युग में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1857 में वहां पुलिस चौकी खोली गई थी। बाद में इस चौकी को वर्ष 1898 में थाने में बदल दिया गया। यहां आने के बाद सीएम ने थाना परिसर में स्थित खंभेश्वरी देवी का पूजन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के लोग अपने किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और होली, दीवाली जैसे पर्व की शुरूआत यहां आकर खंभेश्वरी देवी की पूजा के साथ करते हैं।

इतिहास जानकर बोले, ये दस्तावेज संभालकर रखो

- स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पुलिस थाना बस्तर अंचल में गुण्डाधूर के नेतृत्व में वर्ष 1910 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आंदोलन का भी साक्षी है।
- मुख्यमंत्री ने सिहावा पुलिस थाने के पुराने रोजनामचों, वहां के माल थानों और ग्रामवार रखे पुराने अभिलेखों को भी देखा।
- डॉ. सिंह ने इन पुराने अभिलेखों को ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए इन्हें हमेशा सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

सिपाही को रखना होता था 6 फीट का डंडा

- जब ये थाना बना तब अंग्रेजों ने सिपाही को 6 फीट का डंडा अपने पास रखना मैंडेटरी किया था।
- पैदल सिपाहियों को 4 रुपए का मासिक वेतन देना तय हुआ था।
- उस वक्त रेलवे के स्लीपर्स के निर्माण के लिए सागौन की लकड़ी यहीं से जाया करती थी।
- इसके लिए नैरोगेज रेल पथ भी बनाया गया था जो रायपुर से उड़ीसा के गांव कुंदई तक था।
- उस वक्त यहां वन संपदा पर अंग्रेजों के नियंत्रण के उद्देश्य से ये थाना खोला गया था।
- ये एकमात्र सरकारी भवन था। यहां अंग्रेज अधिकारी आते और ठहरते थे।
- बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड में लोहे की कमी हो गई और ये पटरियां उखाड़कर इंग्लैंड भेज दी गई।

आकाशवाणी से 'रमन के गोठ' की 24वीं कड़ी

पांच हजार दिनों की सफलता का श्रेय आम जनता को : डॉ. रमन

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपनी सरकार के प्रथम पांच हजार दिनों की सफलता का श्रेय आम जनता को दिया है और इसके लिए प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। डॉ. सिंह ने कहा-मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे प्रदेश की जनता और हमारे नेतृत्व ने यह अवसर दिया। जनता की सेवा करने का जो सपना मन में था, उसको पूर्ण करने का मौका देने के लिए मैं प्रदेश की जनता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को दिल की गहराईयों से धन्यवाद देता हूं।

मुख्यमंत्री आज सवेरे आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से अपनी मासिक रेडियो वार्ता 'रमन के गोठ' की 24वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे। उनकी रेडियो वार्ता का प्रसारण राज्य में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और विभिन्न प्राइवेट टेलीविजन तथा एफ.एम. चैनलों द्वारा किया गया। प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में कई स्थानों पर लोगों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री का रेडियो प्रसारण सुना।

डॉ. रमन सिंह ने श्रोताओं को अपनी सरकार के पांच हजार दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने रेडियो प्रसारण में कहा कि श्री वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की परिकल्पना को साकार किया। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को आदर्श राज्य बनाने के उनके सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा-मुझे खुशी है कि आज राज्य के निर्माण और विकास की इस यात्रा में हम सफल हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2003 से अब तक अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा-तब राज्य का बजट केवल सात हजार करोड़ था, आज 80 हजार करोड़ से ज्यादा का हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 47 हजार करोड़ से बढ़कर 250 हजार करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी 12 हजार रूपए से बढ़कर 82 हजार रूपए तक पहुंच गई है। अटल जी ने वर्ष 2000 में देश में तीन नये राज्य बनाए। उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। हमने शासन-प्रशासन की सेवाओं को जनता के नजदीक ले जाने के लिए 11 नये जिलों का निर्माण किया। अब राज्य में 27 जिले हो गए हैं। प्रदेश मे तहसीलों की संख्या 98 से बढ़कर 150, नगर पंचायतों की संख्या 49 से बढ़कर 112, नगर पालिकाओं की संख्या 28 से बढ़कर 43 और नगर निगमों की संख्या दस से बढ़कर 13 हो गई है। डॉ. सिंह ने कहा-जन-धन योजना, मुद्रा योजना, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना सहित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है।

मिनी केबिनेट की तरह हमारे प्राधिकरण : मुख्यमंत्री ने रेडियो श्रोताओं को बताया - पहले से प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा हमने चार विशेष प्राधिकरणों का भी गठन किया है। सरगुजा और उत्तर क्षेत्र, बस्तर और दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करके आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ विकास का रास्ता बन गया है। इन चारों प्राधिकरणों की बैठक एक 'मिनी कैबिनेट' की तरह होती है, जहां समस्याओं के निराकरण के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर निर्णय लेते हैं।

स्कूल-कॉलेजों की संख्या में वृद्धि : मुख्यमंत्री ने कहा-पांच हजार दिनों की यात्रा में राज्य में शिक्षण संस्थाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या 13 हजार से बढ़कर 38 हजार, मिडिल स्कूलों की संख्या पांच हजार से बढ़कर 16 हजार 500, हाईस्कूलों की संख्या 900 से बढ़कर 2600 और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या 600 से बढ़कर 3715 तक पहुंच गई है। बच्चों का ड्रापआउट रेट में 11 प्रतिशत से घटकर सिर्फ एक प्रतिशत रह गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति हुई है। वर्ष 2003 में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था।

उन्होंने कहा-यदि राज्य नहीं बना होता तो, छत्तीसगढ़ को न तो आईआईटी मिलता और न ही ट्रिपल आईटी। प्रदेश में एम्स और आईआईएम की स्थापना हो गई है। सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या तीन से बढ़कर 13 हो गई। सरकारी कॉलेज जो सिर्फ 116 थे। आज 224 तक पहुंच गए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर दस, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 12 से बढ़कर 50, कृषि महाविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर 21, पालीटेक्निक संस्थाओं की संख्या दस से बढ़कर 51,आईटीआई की संख्या 61 से बढ़कर 176 और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावासों और आश्रम शालाओं की संख्या 1837 से बढ़कर 3250 हो गई है।

बिजली का उत्पादन बढ़ा : मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन और विद्युत अधोसंरचनाओं के विकास में राज्य की उपलब्धियों का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली उत्पादन 4732 मेगावाट से बढ़कर 22 हजार 764 मेगावाट तक पहुंच गया है। अति उच्च दाब बिजली उपकेन्द्रों की संख्या 28 से बढ़कर 96 हो गई है। ट्रांसमिशन लाईनों की संख्या 5205 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 11522 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गई है। राज्य की बिजली ट्रांसमिशन क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़कर 6350 मेगावाट और विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 18 लाख से बढ़कर 42 लाख हो गई है। डॉ. रमन सिंह ने श्रोताओं को यह भी बताया कि राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खपत इन पांच हजार दिनों में 350 यूनिट से बढ़कर 1724 यूनिट हो गई है।

मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे नेहरू-गांधी उद्यान

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज सवेरे मैराथन दौड़ के शुभारंभ के बाद मरीन ड्राईव (तेलीबांधा तालाब) से पैदल अपने निवास लौटते समय बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के नेहरू-गांधी उद्यान पहुंचे। वहां उन्होंने भ्रमण के लिए आए नागरिकों से बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री इस दौरान गांधी उद्यान के गेट के बाहर नारियल पानी का ठेला लगाने वाले श्री मनोज के ठेले पर पहुंचे। वहां उन्होंने श्री मनोज के अनुरोध पर नारियल पानी का लुफ्त लिया। श्री मनोज ने उनके साथ सेल्फी भी ली। डॉ. सिंह वहां जवारा, करेला, लौकी, आंवला, चुकन्दर और गाजर का जूस का ठेला लगाने वाले श्री भावेश साहू के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की और उनके आग्रह पर फोटो भी खिंचवाई।

'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना'

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में प्रदेश के मेहनतकश मजदूरों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि शहरों में दैनिक मजदूरों को गर्मागर्म ताजा भोजन देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के 10 जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा, कवर्धा, कोरिया, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और सरगुजा में संचालित होगी। इसके लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सम्मेलन का आयोजन श्रम विभाग द्वारा डॉ. रमन सिंह की सरकार के पांच हजार दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। डॉ. रमन सिंह ने सम्मेलन के बाद श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन भी किया। उन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह भी ऐलान किया कि सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को इलाज के लिए तीन लाख रूपए की राशि दी जाएगी। मेडिकल इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के लिए श्रमिकों के बच्चों की फीस राज्य सरकार देगी। प्रदेश के साढ़े तीन लाख श्रमिकों के के पंजीयन का नवीनीकरण स्वतः ही हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ संवाद/RO-83843/1

प्रकाशक एवं मुद्रक गणेश प्रसाद मिश्रा द्वारा स्वामी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि. के लिए मिशन मीडिया प्रा.लि., छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, रायपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं सी-111, शिव मंदिर के सामने गायत्री नगर, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- विवेक मिश्रा*, आरएनआई रजि. नं.-52143/91, डाक पंजीयन 29/2010-2012, * पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।